समक्ष एम. एम. पुंछी और ए. एल. बाहरी, जेजे.

एन. के. बत्रा और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और अन्य, - उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1989 *का* 6755

16 अगस्त, 1989।

भारत का संविधान, 1950 - *अनुच्छेद* 14, 15 *और* 226 - *प्रवेश में समान अवसर - हरियाणा के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बी.टेक डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश - चयन का आधार प्रवेश परीक्षा से अंकों के सामान्यीकरण की प्रणाली में बदल दिया गया - हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के छात्रों को अनुचित लाभ देकर अनुचित लाभ देने के आधार पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों द्वारा सामान्यीकरण को चुनौती दी गई। संस्थागत वरीयता - प्रणाली, सामान्यीकरण की प्रणाली - क्या* यह कानून के खंड *का उल्लंघन है।*

यह माना गया कि वर्तमान मामले में, चयन का आधार किसी भी सामान्यीकरण पर नहीं है क्योंकि दोनों बोर्डों में से किसी भी मानक यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसा कि मानक अंतर्निहित था, वह औसत खींचकर प्राप्त मानक होगा, जो भी दो बोर्डों में अधिक था। इस प्रकार, हमारे विचार में, सिद्धांत किसी भी स्थिति में सामान्यीकरण नहीं हो सकता

है, ताकि यह प्रवेश के लिए समान अवसरों और अवसरों को बढ़ावा दे सके और इसके बजाय, हमारे विचार में, यह चीजों को असामान्य बना देगा, असमानता को बढ़ावा देगा और प्रवेश के लिए समान अवसर से वंचित करेगा।

(पैरा 9)

हमारे समक्ष रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि यह राज्य सरकार थी जिसने एमडी विश्वविद्यालय पर निर्णय लागू किया था और जिसके कुलपति ने उस पर निर्णय लिया था।

केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रणाली या सामान्यीकरण को अपनाएं। सामान्यीकरण की उनकी समझ दोनों में से अर्थ निकालना था, जैसा कि विश्वविद्यालय के पत्र में दिए गए दो चित्रों से स्पष्ट है, जो कॉइल आई लेग के सिद्धांत को संबोधित करते हैं। प्रवेश विवरणिका में सामान्यीकरण अंततः एमडी विश्वविद्यालय द्वारा समझे और सचित्र सामान्यीकरण से काफी अलग है। इस संबंध में विश्वविद्यालय का कोई औपचारिक निर्णय और राज्य सरकार का कोई औपचारिक निर्णय हमारे समक्ष नहीं रखा गया था। इन परिस्थितियों में सामान्यीकरण अनुचित है, हमारे विचार को बल मिलता है।

(पैरा 11)।

हरियाणा बोर्ड से 10+2 की परीक्षा पास करने वाले छात्रों और केंद्रीय बोर्ड से एक ही परीक्षा पास करने वाले छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए एमडी विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया सामान्यीकरण का सिद्धांत अवैध, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान, 1950 के कला 14 और 15 का उल्लंघन है और इसे रद्द किया जाना

चाहिए।

(पैरा 14)

यह माना जाता है कि सामान्यीकरण की अवधारणा और सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है और हम हरियाणा के क्षेत्रीय कॉलेजों में बी.टेक पाठ्यक्रम में संयुक्त प्रवेश के लिए प्रवेश विवरणिका से इसे हटाने का निर्देश देते हैं और उत्तरदाताओं को पुराने ब्रोशर के आधार पर प्रवेश को अंतिम रूप देने का निर्देश देते हैं।

(पैरा 19)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *226/227 के* तहत सिविल रिट याचिका *में प्रार्थना की गई है कि*: -

(१) (ग*) मामले के रिकॉर्ड को पूरा करने* के लिए हमें *तलब किया गया है।*

(२) *(* उत्तरदाताओं 3 और *4 द्वारा संचालित बी.टेक डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नियमों और प्रक्रिया के खंड* '7 सी और II *(viii) को* रद्द करते हुए, *जिसके तहत* बीटेक पाठ्यक्रम *में प्रवेश के उद्देश्य से उत्तरदाताओं द्वारा अंकों का सामान्यीकरण किया जाना है*) जारी किया जाए।

(३) *मैंडमस की प्रकृति में* > *उत्तरदाताओं को अर्हक परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर बी.टेक डिग्री पाठ्यक्रम सत्र* 1989-90 *में प्रवेश देने का निर्देश दिया गया है, जैसा कि उन कॉलेजों में स्थापित प्रथा है।* *जारी किया जाए।*

(४) *यह भी प्रार्थना की जाती है कि इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, यह माननीय न्यायालय कोई अन्य*

उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करे जैसा कि वह उचित समझता है।

(५) याचिकाकर्ताओं को भी याचिका का अधिकार दिया जा सकता *है।*

*(६) अनुबंध की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने के संबंध में शर्त को **कृपया** हटा दिया जाए।*

(७) मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका की अग्रिम राशि की सेवा से संबंधित शर्त *को हटा दिया जाए।*

याचिकाकर्ताओं की *ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एल. सिब्बल, अधिवक्ता श्री पी. एस. पटवालिया।*

एस. सी. मोहनता, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री ए. मोहंता, अधिवक्ता, *प्रतिवादियों के लिए।*

पाँच. अतिरिक्त उत्तरदाताओं के लिए *पी जैन, वकील।*

निर्णय

लाख। *एम. पुंछी, जे।;*

(एक) 67 याचिकाकर्ताओं द्वारा पसंद की गई इस रिट याचिका में, हरियाणा राज्य के सभी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और छोटू-राम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुरथल (हरियाणा) में 4-वर्षीय अंडर-ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयन के आधार के रूप में 'सामान्यीकरण' की नई शुरू की गई घटना को चुनौती दी गई

है।

(दो) यहां अधिकांश याचिकाकर्ता नाबालिग हैं और उन्होंने अपने माता-पिता या अभिभावकों के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य के निवासी हैं और हरियाणा राज्य के विभिन्न स्कूलों में छात्र हैं। वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली (संक्षेप में, 'केंद्रीय बोर्ड' के रूप में संदर्भित) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में 10 + 2 प्रणाली की 12 वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित हुए थे, क्योंकि उनके स्कूल उस बोर्ड से संबद्ध थे। एक अन्य प्रणाली जो केंद्रीय बोर्ड प्रणाली के समान है, अन्य स्कूलों के माध्यम से हरियाणा राज्य में चल रही है। छात्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (संक्षेप में, जिसे 'हरियाणा बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया जाता है) द्वारा आयोजित वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा में उपस्थित होते हैं, क्योंकि उनके स्कूल उस बोर्ड से संबद्ध होते हैं। केंद्रीय बोर्ड और हरियाणा बोर्ड दोनों ने एक ही पाठ्यक्रम और परीक्षा के समान पैटर्न को अपनाया है। हरियाणा राज्य के भीतर स्थित स्कूलों से इन दो परीक्षाओं को पास करने वाले छात्र बीटेक नामक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इन परीक्षाओं को किस उद्देश्य के लिए समकक्ष माना जाता है?

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

से संबद्ध प्रतिवादी संख्या 3, प्रतिवादी नंबर 1 और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबद्ध छोटू राम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुरथल, प्रतिवादी नंबर 2 में प्रवेश।

(तीन) याचिकाकर्ताओं के अनुसार, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बी.टेक पाठ्यक्रमों के लिए कुल 310 सीटें हैं®। कुरुक्षेत्र, जिसमें से 155 (एक-आधा), हरियाणा के छात्रों के लिए रखा गया है और अन्य 155 पूरे देश के छात्रों के लिए खोले गए हैं। इसी तरह मुरथल स्थित छोटूराम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हरियाणा के छात्रों के लिए 150 सीटें रखी गई हैं। इन 305 सीटों के अलावा, देश के अन्य हिस्सों में अन्य क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में हरियाणा के छात्रों को 58 अन्य सीटें आवंटित की जाती हैं। इस तरह हरियाणा के छात्रों के लिए 363 सीटें हैं। तुम तक . 1989 में इन सीटों को केंद्रीय बोर्ड और हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त योग्यता अंकों से निर्धारित योग्यता के आधार पर भरा गया था। वर्तमान शैक्षिक सत्र 1989-90 से दोनों कॉलेजों ने दोनों बोर्डों के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के सामान्यीकरण की प्रणाली का पालन करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एमडी विश्वविद्यालय, रोहतक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 4 नवंबर, 1988 को आयोजित अपनी बैठक में अंकों के सामान्यीकरण की प्रणाली का पालन करने का फैसला किया। लेकिन यह तथ्य अप्रैल 1989 में ही प्रेस

में सामने आया, हिंदी में भी नहीं। अंग्रेजी अनुभाग, हालांकि यह कुछ हद तक अस्पष्ट था। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि भारत सरकार ने 15 मार्च, 1989 के एमसीटीओ विज्ञापन एनेक्सी: आरई पी -3 पर कहा था कि क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में सत्र 19899 90 के लिए प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। मई, 1989 में दोनों कॉलेजों में संयुक्त प्रवेश के लिए प्रवेश विवरणिका प्रकाशित की गई, जिसमें खंड 7 के माध्यम से चयन युद्ध का आधार रखा गया, जिसे सामान्यीकरण के रूप में जाना जाता है। इस स्तर खंड 7 में पुनरुत्पादन करना उचित होगा:

> एक. 7) सभी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश, सूचीबद्ध। उपरोक्त पैरा 1 में, नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार सामान्यीकृत अंकों की योग्यता के आधार पर बनाया जाएगा: -
>
> दो. शीर्ष (X) छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, जैसा कि नीचे पैरा 2 में विस्तृत है, भौतिकी के विषय में, अखिल भारतीय वरिष्ठ के साथ 10 + 2 परीक्षा में उपस्थित होते हैं
>
> सीबीएसई, नई दिल्ली की स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा और स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, भिवानी की वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा प्राप्त की जाएगी और दोनों परीक्षाओं में से प्रत्येक के लिए

अलग-अलग औसत निकाला जाएगा। सीबीएसई, नई दिल्ली की अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए पीआई और स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, भिवानी की वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए पी 2 को पीआई माना जाता है। इसी तरह रसायन विज्ञान और गणित के विषयों में औसत निकाला जाएगा। मान लीजिए कि ये दोनों बोर्डों के लिए क्रमशः रसायन विज्ञान में सीएल सी 2 और गणित में एम 2 हैं।

पीआई, सीएल और एमएल को 3 से विभाजित करने पर सीबीएसई, नई दिल्ली की अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में अंकों का समग्र औसत होगा। इसी तरह पी 2 जोड़कर। स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, भिवानी की वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा के भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में अंकों के कुल औसत से 3 से विभाजित करने पर सी 2 और एम 2 प्राप्त किया जाएगा। ये समग्र औसत सामान्यीकरण के प्रयोजनों के लिए संबंधित बोर्डों के संदर्भ चिह्नों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

इन्हें A और B इस प्रकार होने दें कि A दोनों से ऊँचा

हो।

तीन. इन बोर्डों के विज्ञान, स्ट्रीम में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों (एक्स) की संख्या, जिनके अंकों का उपयोग सामान्य परीक्षा के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, प्रति हजार दो तक सीमित होंगे, न्यूनतम 20 और अधिकतम 100 के अधीन।

चार. फिर प्रवेश के लिए एक आवेदक के भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में वास्तविक अंक निम्नानुसार सामान्यीकृत किए जाएंगे: -

यदि कम संदर्भ औसत वाले बोर्ड के किसी उम्मीदवार के वास्तविक पीसीएम अंक 'एम' हैं, तो उसका ए सामान्यीकृत अंक M X होंगे --- क्या आप जानते हैं

जन्म

उच्च संदर्भ औसत के साथ बोर्ड से अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए।

चार: अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के संबंध में सामान्यीकरण: -

(अ) सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के अलावा किसी अन्य बोर्ड / परीक्षा निकाय से;

(आ) वर्ष 1989 से एक वर्ष पहले अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा, सीबीएसई और स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा के वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा सहित किसी भी बोर्ड/परीक्षा निकाय से उपरोक्त उदाहरण में दो संदर्भ अंकों में से उच्च अर्थात 'ए' के संदर्भ में की जाएगी।

यदि दो उम्मीदवार कुल अंकों का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं, तो निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा: -

(१) उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा।

(२) यदि (i) के तहत प्रवेश उस उम्मीदवार को नहीं दिया जा सकता है जो रक्षा कर्मियों या वफद/बच्चे या सिविल जीटी कॉयस एएससी का बच्चा या आश्रित भाई/बहन है, जो एक नागरिक श्रेणी ।।। या चतुर्थ श्रेणी का सरकारी सेवक था और सैन्य कर्मियों के समान शर्तों के तहत क्षेत्र क्षेत्रों में सेवा की है और जो 1985 में पाकिस्तान के साथ शत्रुता के दौरान या युद्ध के दौरान मारा गया है या स्थायी रूप से अक्षम हो गया है। 1971 को

स्वीकार किया जाएगा। आवेदन करते समय, ऐसे उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में संबंधित क्षेत्र के सचिव, जिला 'सैनिक, नाविक और एयरमैन बोर्ड से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(३) 1. यदि उपरोक्त (i) और (ii) में 1 मानदंड लागू नहीं होते हैं, तो आयु में बड़े उम्मीदवार को प्रवेश दिया जाएगा।

(४) यदि (iii) पर मानदंड भी लागू नहीं होता है, तो अंग्रेजी विषय में उच्च प्रतिशत अंकों वाले उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा।

केवल उन्हीं परीक्षाओं पर विचार किया जाएगा जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती हैं।

(चार) याचिका में, अंकों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया को यह दिखाने के लिए स्पष्ट रूप से टिप्पणी की गई है कि बेहतर शैक्षणिक क्षमता को कुचला जा रहा था और एकमात्र उद्देश्य हरियाणा बोर्ड के छात्रों को एक महत्व प्रदान करना था क्योंकि केंद्रीय बोर्ड के छात्रों का परिणाम हमेशा अधिक था। इसके अलावा, यह दावा किया गया था कि सामान्यीकरण की प्रणाली पूरी तरह से मनमानी, अवैध और संविधान के

अनुच्छेद 14 का उल्लंघन थी और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता था। आगे कहा गया कि जब निवास की आवश्यकता समान थी और दोनों परीक्षाएं समान थीं, तो हरियाणा बोर्ड के छात्रों के पक्ष में अनुचित भेदभाव किया जा रहा था, और हरियाणा बोर्ड के छात्रों के पक्ष में यह संस्थागत प्राथमिकता सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के खिलाफ थी। अंत में, यह दावा किया गया था कि इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने वाले दोनों विश्वविद्यालयों के सभी पाठ्यक्रमों के लिए, यह केवल बीटेक पाठ्यक्रम में है कि सामान्यीकरण की अवधारणा शुरू की गई थी, जबकि अन्य पाठ्यक्रमों में, परीक्षाओं को समान रखा गया था।

(पाँच) प्रतिवादियों को प्रस्ताव सुनवाई में भेजा गया था। हरियाणा बोर्ड के कुछ छात्रों को भी उत्तरदाताओं के रूप में जोड़ने की अनुमति मिल गई है। मोशन बेंच ने मामले को एक डिवीजन बेंच को स्वीकार कर लिया, ताकि इसे जुलाई 1989 में ही निपटाया जा सके। एक अंतरिम निर्देश जारी किया गया था कि पूरी चयन प्रक्रिया जारी रह सकती है और प्रतिवादी भर्ती किए गए उम्मीदवारों की एक सूची तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसे अगले आदेश तक प्रकाशित नहीं किया जाएगा। उस आदेश के अनुसरण में यह याचिका हमारे समक्ष रखी गई है।

(छः) प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर रिटर्न में यह

स्वीकार किया गया है कि दोनों परीक्षाओं यानी केंद्रीय बोर्ड और हरियाणा बोर्ड को बीटेक डिग्री पाठ्यक्रमों की पात्रता के उद्देश्य से समकक्ष माना जाता है। इसके बावजूद, प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा यह कहा जाता है कि प्रवेश के लिए योग्यता तैयार करने के उद्देश्य से) केंद्रीय बोर्ड और हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को न्याय के हित में सामान्यीकृत किया जाना है। प्रतिवादी संख्या 3 ने इस बात से इनकार नहीं किया कि संबंधित दो कॉलेजों में उल्लिखित आधी सीटों के लिए केवल वे छात्र जिन्होंने हरियाणा राज्य में स्थित स्कूलों से 10-जे -2 परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वे प्रवेश लेने के लिए पात्र थे। सामान्यीकरण के सिद्धांत के संबंध में, यह दावा किया गया था कि 4 नवंबर, 1988 को एमडी विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने प्रक्रिया को स्वीकार करने का संकल्प लिया, और मामले को प्रकाशन के लिए प्रेस को भेजा गया। अंग्रेजी और हिंदी सेक्शन में विसंगति को अनजाने में बताया गया था। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने *2 मई, 1989 के पत्र के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा तैयार किए गए सामान्यीकरण सिद्धांत को अनुमोदित किया था।*

यह कहा गया था कि यह हरियाणा सरकार थी जिसने इच्छा व्यक्त की थी कि प्रवेश अंकों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। 3 ने अपनी वापसी में जोर देकर कहा कि नया मानदंड न्यायसंगत, न्यायसंगत है और राज्य के सभी छात्रों के लिए प्रवेश के समान अवसर और अवसर सुनिश्चित करता है। इस तरह के कदम के कारण का भी खुलासा किया गया था। यह कहा गया कि हरियाणा बोर्ड से पास होने वाले छात्रों में बहुत नाराजगी थी कि उन्हें प्रवेश के मामले में समान अवसर देकर समान रूप से व्यवहार नहीं किया जा रहा था क्योंकि कोई सामान्य संदर्भ नहीं था, क्योंकि दोनों बोर्ड परीक्षाओं के अलग-अलग निकाय थे। इस प्रकार, विसंगति को दूर करने के लिए सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी ताकि दोनों बोर्डों के उम्मीदवारों को प्रवेश के मामले में समान अवसर देने के लिए एक सामान्य संदर्भ हो।

(सात) यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि दोनों बोर्डों द्वारा परिणामों की घोषणा से पहले ही पक्षकार अदालत में थे। यह सुझाव दिया गया था कि याचिकाकर्ता उस स्तर पर परिणाम के मूल्य को नहीं मान सकते थे, और पिछले परिणामों पर याचिकाकर्ताओं की टिप्पणी काल्पनिक और दूर की थी। दोनों सुझावों या याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हरियाणा बोर्ड से अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को कोई महत्व दिया

गया था या उस संबंध में कोई संस्थागत वरीयता दी गई थी, रिटर्न में दृढ़ता से खारिज कर दिया गया था।

(आठ) याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर प्रतिकृति में, प्रतिवादियों के दावे का खंडन किया गया था और एक क्रॉस दावा किया गया था कि कॉलेजों के प्रिंसिपलों ने 17 मई, 1989 को प्रवेश विवरणिका वितरित की थी, लेकिन निदेशक मंडल ने बाद में 26 मई, 1989 को निर्णय लिया। याचिका में दिए गए उदाहरण को फिर से जोर दिया गया और फिर से शुरू किया गया।

(नौ)हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एचएल सिब्बल और हरियाणा के महाधिवक्ता श्री एस. सी. मोहनता के अलावा अतिरिक्त प्रतिवादियों के लिए श्री एस. पी. जैन को काफी विस्तार से सुना है। बार में यह स्वीकार किया गया कि इस अवधारणा या सामान्यीकरण को देश में कहीं भी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए नहीं अपनाया गया है, जिन्हें देश के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा चिह्नित किया गया है। ' उद्धृत एकमात्र उदाहरण यह था कि बिड़ला संस्थान, पिलानी में एक सिद्धांत के रूप में सामान्यीकरण काम कर रहा था, और इसके पीछे तर्क पर जोर देने के लिए इसका एक उद्धरण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इससे पहले कि इस पर ध्यान दिया

जाए, हमें यह समझने की जरूरत है कि 'सामान्यीकरण' क्या है। जैसा कि हम इसे उच्चारण के दृष्टिकोण से देखते हैं, सामान्यीकरण का स्रोत शब्द 'आदर्श' है। वही

शब्द 'आदर्श: हैं: एक नियम: एक पैटर्न: एक आधिकारिक मानक, इरोमी 'आदर्श' शब्द 'सामान्य' आता है जो सह में है। एनटेक्स्ट का अर्थ है: शासन करने के लिए या आधिकारिक मानक के अनुसार एसोरुमग। उसी संदर्भ में, 'सामान्यीकरण' शब्द का अर्थ होगा: इसे नियम के अनुरूप बनाना या इसे आधिकारिक मानक पर लाना। शब्दावली के दृष्टिकोण से, विवरणिका के खंड 7 में जो कहा गया है, वह शायद ही सामान्यीकरण है और उसमें अपनाया गया सिद्धांत सामान्यीकरण के अलावा कुछ और हो सकता है। कम से कम, इसे गलत शीर्षक या नामकरण किया गया है। नियमों में किसी ऐसे मानक या कमी की परिकल्पना नहीं की गई है जिसके आधार पर दूसरे का सामान्यीकरण किया जा सके। अब इस मोड़ पर बिड़ला संस्थान, पिलानी में प्रचलित ऊपर उल्लिखित 'सामान्यीकरण' देखें:

> "सामान्यीकरण: देश में विभिन्न परीक्षा अधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों को दिए गए पूर्ण अंकों के बीच असमानता मौजूद है, यह सर्वविदित है। ऐसे सभी उम्मीदवारों को तुलना के समान पैमाने पर लाने के लिए संस्थान एक दशक से अधिक समय से एक समय-सम्मानित और प्रसिद्ध प्रणाली का अभ्यास कर रहा है जिसे सामान्यीकरण के रूप में जाना जाता है। यह मूल रूप से उस उम्मीदवार से उम्मीदवार के सापेक्ष विस्थापन का पता लगाने की कोशिश करता

है जो सार्वजनिक परीक्षा में पहले स्थान पर रहा था, जिसे समीक्षा के तहत उम्मीदवार ने उत्तीर्ण किया है। यदि इनमें से प्रत्येक मामले में उम्मीदवारों की संख्या काफी बड़ी है, तो यह एक सही सांख्यिकीय मामला होगा, जिसमें एक बोर्ड में पहली रैंक के छात्र की आंतरिक योग्यता समान आकार के किसी अन्य बोर्ड में पहली रैंक के छात्र के बराबर होगी। व्यवहार में संस्थान एक अखिल भारतीय संस्थान के रूप में केंद्रीय बोर्ड (जो संयोग से वर्ष-दर-वर्ष छात्रों का सबसे बड़ा एकल योगदानकर्ता है) और भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा को मान्यता देता है ताकि किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार के प्रतिशत अंकों को उस स्ट्रीम के लिए उस बोर्ड में पहले छात्र के प्रतिशत अंकों के प्रतिशत अंकों के आधार पर सामान्य किया जा सके, जिसमें कम से कम भौतिकी शामिल है। रसायन विज्ञान और गणित और अंग्रेजी यदि यह उस बोर्ड के प्रसाद में प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित स्थितियों के संबंध में संस्थान सुरक्षित रखता है। कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर सामान्यीकरण करने का अधिकार जो वर्तमान वर्ष के लिए सबसे अधिक है:

(क) जहां नामित बोर्डों के संबंध में सही सूचना नियत तिथि के भीतर उपलब्ध नहीं है, या तो कारण यह प्रदान नहीं की गई है या सूचना है।

केवल एक धारा के संबंध में जिसका भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के संयोजन से कोई संबंध नहीं है।

(आ)जहां एक राज्य बोर्ड या उसके समकक्ष मौजूद नहीं है और कार्य राज्य के कई परीक्षा अधिकारियों द्वारा साझा किया जाता है, उनमें से कोई भी सांख्यिकीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं है।

(इ) जहां सार्वजनिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश पर विचार किया जा रहा है जो वर्तमान वर्ष की मुख्य परीक्षा से अलग है।

इससे यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय बोर्ड में प्रथम रैंकिंग वाले छात्र, एक ऐसी धारा जिसमें कम से कम भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी शामिल होती है, को केन्द्रीय बोर्ड के अलावा अन्य बोर्डों में विद्याथयों द्वारा प्राप्त अंकों के सामान्यीकरण के लिए मॉडल माना जाता है। यही कारण है कि यदि ऐसे प्रत्येक मामले में उम्मीदवारों की संख्या काफी अधिक थी, तो यह एक सही सांख्यिकीय मामला होगा जिसमें एक बोर्ड में पहली रैंक के छात्र की आंतरिक योग्यता को समान आकार के किसी अन्य बोर्ड में पहली रैंक के छात्र के बराबर किया जाएगा। लेकिन इस मामले में, चयन का आधार किसी भी सामान्यीकरण पर नहीं है क्योंकि दोनों बोर्डों में से किसी के लिए भी कोई मानक मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

बजाय हरियाणा के एडवोकेट-जनरल द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि जो मानक अंतर्निहित था, वह औसत खींचकर प्राप्त मानक होगा, जो भी दोनों बोर्डों में अधिक था। इस प्रकार विकसित सिद्धांत, हमारे विचार में, किसी भी स्थिति में सामान्यीकरण नहीं हो सकता है, ताकि यह प्रवेश के लिए समान अवसरों और अवसरों को बढ़ावा दे सके और इसके बजाय, हमारे विचार में, यह चीजों को असामान्य बना देगा, असमानता को बढ़ावा देगा और प्रवेश के लिए समान अवसर से वंचित करेगा।

(दस) यहां यह जोड़ना उपयोगी होगा कि रिटर्न में कही गई बातों पर जोर देने के अलावा, हरियाणा के महाधिवक्ता हमारे बार-बार कहने के बावजूद, हमारे बार-बार कहने के बावजूद, हमारे सामने कोई वैध सामग्री पेश नहीं कर सके, **जो** उत्तरदाताओं को इस सामान्यीकरण सिद्धांत को अपनाने के लिए राजी करने के लिए गई होती। हालांकि, उन्होंने हमारे सामने दो पत्रों की फोटोस्टेट प्रतियां रखीं, जिनमें से एक 26 अगस्त, 1988 के शिक्षा सचिव (तकनीकी प्रभाग) से है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 4 को निर्देश दिया गया था कि आने वाले शैक्षणिक वर्ष में कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बजाय सामान्यीकरण का सहारा ले सकता है, जिसके बारे में वह पहले ही प्रिंसिपल से मौखिक रूप से बात कर चुका है। अब यह किसी का मामला नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए कभी कोई प्रवेश परीक्षा हुई थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को इस प्रकार की सूचना

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

गलत तरीके से दी गई थी। प्रवेश परीक्षा एक ऐसी स्थिति को कवर करने के लिए स्वीकृत तरीकों में से एक है जहां उम्मीदवार विभिन्न विश्वविद्यालयों और विभिन्न हिस्सों से आते हैं। देश, शिक्षा के मानकों के आधार पर अलग-अलग योग्यता अंक और चीजों की प्रकृति में भिन्न अंक। दूसरा पत्र एमडी विश्वविद्यालय, रोहतक के सहायक रजिस्ट्रार (अकादमिक) की ओर से कॉलेज के प्रिंसिपल-प्रतिवादी नंबर 4 को निम्नलिखित आशय का है: -

> मैं आपके पत्र संख्या 12का उल्लेख करना चाहता हूं। (ग) उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28 अप्रैल, 1988 के ईसीएम/1752 के आदेश के अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया संबंधी मामले पर कुलपति द्वारा विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जाएगा। केवल सत्र 1988-89 के लिए अंकों के सामान्यीकरण के बाद। अगले सत्र से प्रवेश के तरीके की समीक्षा विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद द्वारा की जाएगी।

अंकों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

"एक विशेष शैक्षणिक सत्र में प्री-मेडिकल/10 + 2 (या समकक्ष) विश्वविद्यालय 'एक्स' में एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त उच्चतम कुल अंक = 90 प्रतिशत। विश्वविद्यालय 'X' के किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंक (सभी विषयों में) = 65 प्रतिशत किसी अन्य उम्मीदवार के सामान्य अंक

65

= 100 = 72.22 प्रतिशत

90

विश्वविद्यालय 'Y' के प्री-मेड/10+2 (या समकक्ष) में एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त उच्चतम कुल अंक = 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय 'Y' के किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंक (सभी विषयों में) = 60 प्रतिशत किसी अन्य उम्मीदवार के सामान्य अंक

60

= - x 100 = 75 प्रतिशत

80

वास्तव में, विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानदंड तय करना विश्वविद्यालय का एकमात्र कार्य है।

तदनुसार मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

उपर्युक्त पत्र से यह स्पष्ट है कि यह राज्य सरकार थी

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

जिसने एमडी विश्वविद्यालय पर निर्णय लागू किया था और जिसके कुलपति ने इसे केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अपनाने का निर्णय लिया था। सामान्यीकरण की उनकी समझ दोनों में से अर्थ निकालना था, जैसा कि इसमें दिए गए दो दृष्टांतों से स्पष्ट है। प्रवेश विवरणिका में नोमावलाइजेशन अंततः एमडी विश्वविद्यालय द्वारा समझे और सचित्र सामान्यीकरण से काफी अलग है। महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा विश्वविद्यालय का कोई औपचारिक निर्णय और उस संबंध में राज्य सरकार का कोई औपचारिक निर्णय या इस विषय पर कोई अन्य पत्राचार हमारे समक्ष नहीं रखा गया था। इन परिस्थितियों में, ऊपर लिया गया हमारा दृष्टिकोण मजबूत होता है, लेकिन अभी भी कुछ न्यायिक निर्णयों के बल पर इसकी जांच करने की आवश्यकता होगी।

(बारह) मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के क्षेत्र में, सुप्रीम कोर्ट ने *डॉ. जगदीश सरन और अन्य* बनाम *भारत संघ और अन्य* (1) मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के आधार पर राज्य की कार्रवाई का परीक्षण करने का अवसर दिया था। माना जाता है कि चिकित्सा शिक्षा के लिए जो अच्छा है वह तकनीकी शिक्षा के लिए अच्छा है और कुछ मामलों में तकनीकी शिक्षा को चिकित्सा शिक्षा के बराबर बताया गया है। उक्त मामले में, भारत संघ की दलील को खारिज कर दिया गया था और इसका बहाना था कि उसने 70 प्रतिशत की उच्च ऊंचाई पर विश्वविद्यालय-वार आरक्षण का सहारा लिया था क्योंकि यह एक आंदोलन का सामना कर रहा था।

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

इस संबंध में भारत संघ की याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि

> "... अधिकारियों के संवेदनाहीन विवेक को गंभीर चोट पहुंचाने और तत्काल उपचार की आवश्यकता को तेज करने में आत्मा शक्ति की भूमिका को स्वीकार करते हुए, हम दिल्ली विश्वविद्यालय की 'आरक्षण' रणनीति को केवल इसलिए बरकरार नहीं रख सकते क्योंकि सरकार को छात्रों के 'अनशन' का सामना करना पड़ रहा था और मंत्री एक समझौते का फार्मूला चाहते थे और विश्वविद्यालय निकायों ने बस "आमीन" कहा। संस्थागत आरक्षण की संवैधानिकता शैक्षिक जीवन के तथ्यों और समान अवसर की सामाजिक गतिशीलता पर आधारित होनी चाहिए।

राजनीतिक घबराहट *वास्तव में* संवैधानिक तर्क नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त तर्क के बल पर, हम हरियाणा सरकार या प्रतिवादियों की कार्रवाई को केवल इसलिए बरकरार नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें पता चला कि हरियाणा बोर्ड से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में बहुत नाराजगी थी क्योंकि उन्होंने सोचा था कि प्रवेश के मामले में समान अवसर देकर उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा था क्योंकि कोई सामान्य संदर्भ नहीं था। परीक्षा के प्रयोजनों के लिए दो बोर्ड अलग-अलग निकाय हैं। हरियाणा बोर्ड के छात्रों की नाराजगी कुछ भी नहीं है। और मान लीजिए कि केंद्रीय बोर्ड के छात्रों द्वारा

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

एक क्रॉस नाराजगी और आंदोलन किया गया था। यह *भी* कुछ नहीं होता। उत्तरदाताओं की कार्रवाई को शैक्षिक जीवन के तथ्यों पर बचाव करने की आवश्यकता थी और दुर्भाग्य से कोई भी हमारे सामने नहीं रखा गया था। इसके बजाय याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि चूंकि प्रतिशत के मामले में हरियाणा बोर्ड के उम्मीदवारों ने केंद्रीय बोर्ड के उम्मीदवारों की तुलना में कम प्रदर्शन किया है और लागू की गई कार्रवाई हरियाणा बोर्ड के उम्मीदवारों को वरीयता या वेटेज देने के लिए थी, महाधिवक्ता द्वारा दृढ़ता से खारिज कर दिया गया था। हरियाणा, जोर देकर। उन्होंने कहा कि राज्य और उत्तरदाताओं की एक या दूसरे बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए कोई प्राथमिकता नहीं थी और हरियाणा बोर्ड के उम्मीदवारों को कोई अप्रत्यक्ष महत्व नहीं दिया जा रहा था और न ही हरियाणा बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए कोई संस्थागत वरीयता दी जा रही थी। अन्यथा भी, हमारा विचार है कि संस्थागत प्राथमिकता कैसे हो सकती है जब दोनों बोर्ड स्वायत्त थे, किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं थे, चाहे वह हरियाणा राज्य के भीतर हो या इसके बिना। यह केवल आकस्मिक है कि दोनों बोर्डों से परीक्षा की 10 + 2 प्रणाली उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में बी.टेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं और लंबे समय से समानता के आधार पर स्वीकार करते हैं।

(तेरह) *जगदीश सरन के मामले* (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि विश्वविद्यालय-वार अधिमान्य

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

व्यवहार अभी भी अवसर की समानता के नियम के अनुरूप हो सकता है, जहां इसकी गणना असंतुलन या बाधा को ठीक करने और बड़े अर्थों में समानता की अनुमति देने के लिए की जाती है। उस बड़े अर्थ में, सुप्रीम कोर्ट ने जगदीश सरन की याचिका को खारिज कर दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पास अपने ही विश्वविद्यालय के छात्रों को एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में 70 प्रतिशत सीटें प्रदान करने में कोई असंतुलन या बाधा नहीं है। अदालत ने अपने फैसले को इस तथ्य पर आधारित किया कि दिल्ली में छात्र 'धरती पुत्र' नहीं थे, बल्कि उन व्यक्तियों के बेटे और बेटियां थे, जिन्हें जानबूझकर नहीं खींचा गया था।

(चौदह) उनके नियंत्रण से परे कारणों के लिए राजधानी शहर में प्रवेश करना और इस प्रकार सवाल उठाया गया आरक्षण गुणात्मक रूप से अलग था। इस मामले में, दोनों बोर्डों के छात्र 'भूमि पुत्र' हैं और केवल यह तथ्य कि उन्होंने एक या ओटलजेर बोर्ड से अर्हता प्राप्त की है, उन्हें क्षेत्रीय कॉलेजों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए पुरानी समानता की उपस्थिति में अलग से वर्गीकृत नहीं करता है। हरियाणा के एडवोकेट-जनरल का यह कहना कि वर्गीकरण उचित था, तर्कसंगत उत्तर से परे है कि वर्गीकृत करने के लिए क्या सांठगांठ थी और तथाकथित सामान्यीकरण को लागू करने में क्या उद्देश्य हासिल करने की कोशिश की गई थी।

(पंद्रह) अगला मामला; ढांड में मामला) डॉ *डी प्रदीप जैन आदि हैं। जे* बनाम ओ *यूनियो इंडिया और अन्य* (2)। सुप्रीम

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

कोर्ट ने इस मामले में, हालांकि अस्थायी रूप से, निवास आवश्यकताओं के आधार पर आरक्षण का एक निश्चित प्रतिशत बरकरार रखा, ताकि व्यापक आधार पर चिकित्सा प्रवेश के अवसरों को समान किया जा सके और वास्तविक और औपचारिक, वास्तविक नहीं बल्कि केवल कानूनी, समानता लाई जा सके। लेकिन निवास आवश्यकताओं के आधार पर आरक्षण के इस प्रतिशत में, निम्नानुसार अवलोकन करके एक समावेश किया गया था: -

"... इस अदालत पर किए गए आरक्षण के प्रतिशत में उसी विश्वविद्यालय के पीयूसी या प्री-मेडिकल परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए संस्थागत आरक्षण या राज्य के मेडिकल कॉलेजों के शैक्षिक भीतरी इलाकों की स्कूल प्रणाली से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना भी शामिल हो सकता है और इस उद्देश्य के लिए, राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

फैसले के बाद के हिस्से में इस आशय पर जोर देते हुए, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने कहा:

- "... इस उद्देश्य के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अर्हक परीक्षा राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, क्योंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हम

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

यह बता सकते हैं कि बहस के अंत में हमने विद्वान अटॉर्नी जनरल से न्यायालय को सूचित करने के लिए कहा कि इस तरह के आरक्षण के मामले में भारत सरकार और विद्वान अटॉर्नी का क्या रुख था।"

न्यायालय द्वारा की गई जांच के जवाब में जनरल ने एक नीति गत वक्तव्य दायर किया जिसमें भारत सरकार की नीति का निम्नलिखित सूत्रीकरण शामिल था:

केंद्र सरकार आमतौर पर उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए अधिवास या निवास के आधार पर आरक्षण के सिद्धांत का विरोध करती है, चाहे वह पेशेवर हो या अन्य। व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं सहित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की प्रणाली की क्षेत्रीय रूप से व्यक्त प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, तथापि, संस्थानों की शैक्षिक प्रणाली में स्कूल प्रणाली से संबंधित छात्रों के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में उचित मात्रा के लिए आरक्षण या वरीयता निर्धारित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

उपरोक्त उद्धरण के आधार पर, हमारे लिए यह कहना वैध होगा कि हरियाणा बोर्ड से 104-2 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों और केंद्रीय बोर्ड से एक ही परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह न केवल

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

उच्चतम न्यायालय का अधिदेश है बल्कि भारत सरकार की भी नीति है। इस परिस्थिति के कारण, उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिटर्न के साथ पत्र अनुलग्नक आर -4, सहायक शैक्षिक सलाहकार का एक पत्र है। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र के प्राचार्य को यह जानकारी दी। यह कहते हुए कि मंत्रालय को सत्र 1989-90 के लिए 4 वर्षीय बीटेक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उल्लिखित अर्हक अंकों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाने पर कोई आपत्ति नहीं है। कॉलेज द्वारा किया गया यह महत्वहीन हो जाता है और किसी भी श्रेय के योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड के छात्रों को समान रखने के लिए विशेष रूप से यह फैसला सुनाना कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत सरकारी नीति पर आधारित नहीं था, बल्कि एक विचार था जिसे पहले से ही स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया गया था। इसलिए, *डॉ. प्रदीप जैन के मामले* में आधिकारिक फैसले के सामने। (सुप्रा) हरियाणा और केंद्रीय बोर्ड के छात्रों द्वारा उनकी संबंधित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के मामले में उनके बीच मौजूद समानता को भंग करने का कोई भी प्रयास, उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत होगा, और इस आधार पर सामान्यीकरण का सिद्धांत अवैध है, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन। इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

(सोलह) । हरियाणा के महाधिवक्ता ने डॉ. *दिनेश कुमार और अन्य* बनाम *मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (3) पर यह तर्क देते हुए कड़ी आपत्ति जताई कि* डॉ. प्रदीप जैन के मामले (सुप्रा) के *बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद* देखा था कि विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में प्रचलित न्याय के मानकों में अंतर है। विशेष रूप से, रिपोर्ट के पैराग्राफ 6 को सेवा में लगाया गया था। उसमें यह निम्नानुसार देखा गया था :-

•'... इसलिए, हम विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित विभिन्न एमबीबीएस परीक्षाओं में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किए जा रहे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 50 प्रतिशत गैर-आरक्षित सीटों के प्रवेश को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। इस तरह के प्रवेश स्पष्ट रूप से अमान्य होंगे क्योंकि अवसर की समानता से इनकार किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समानता खंड की मांगों को पूरा करने के लिए, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 50 प्रतिशत गैर-आरक्षित सीटों पर प्रवेश एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों की योग्यता के तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिए।

श्री मोहनता ने जोर देकर कहा कि प्रवेश परीक्षा के बजाय, हरियाणा राज्य और उत्तरदाताओं ने सामान्यीकरण का सहारा लिया था क्योंकि प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत समय, ऊर्जा और

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

खर्च की आवश्यकता होती है, जिसे टाला जा सकता है। श्री मोहनता का तर्क इस मूल बात को भूल जाता है कि जब देश भर के विश्वविद्यालय एमबीबीएस पाठ्यक्रम के बाद स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए पूरे भारत में छात्रों की आपूर्ति करने में शामिल थे, तो न्यायिक रूप से यह मानना अपरिहार्य था कि न्याय का मानक आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में भिन्न होगा और एकरूपता की कमी के कारण छात्रों की योग्यता के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए कुछ प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता है और प्रवेश परीक्षा विकसित की गई थी। जवाब के रूप में। यहां, ऐसा कोई ^यूशन उत्पन्न नहीं होता है। रिटर्न में एक शब्द भी नहीं है कि दोनों बोर्डों के बीच न्याय का कोई अलग मानक था या एक बोर्ड अंकन में सख्त था और दूसरा नहीं था। 10 + 2 परीक्षाओं के संबंध में शिक्षा के स्तर, परीक्षा पत्रों के मानक या दो संबंधित बोर्डों में अंकन के मानक के बारे में रिटर्न काफी चुप है। प्रवेश द्वार न होने पर इस पहलू को और विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

परीक्षा का सहारा लिया जा रहा है और हरियाणा बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड के छात्रों के बीच किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए डॉ. प्रदीप जैन के मामले *(सुप्रा) के सामने किसी का सहारा नहीं लिया जा सकता* है । यह जोड़ना उपयोगी होगा कि केंद्रीय बोर्ड पूरे देश में उम्मीदवारों को पूरा करता है: ऐसे क्षेत्र जो विकसित और अविकसित हैं, और यह नहीं माना जा सकता है कि इसका सबसे प्रतिभाशाली छात्र विकसित क्षेत्रों

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

का उत्पाद था, न कि अविकसित क्षेत्रों का। मानव बुद्धि किसी भौगोलिक विभाजन का विशेषाधिकार नहीं है। और इसके अलावा, केन्द्रीय बोर्ड स्वयं दिल्ली नहीं है और यहां तक कि छात्र-वार दिल्ली भी एक लघु भारत है। इस स्कोर से भी, हमें श्री मोहन्ता के तर्क में कोई दम नजर नहीं आता और हम इसे अस्वीकार करते हैं।

(सत्रह) श्री मोहंता ने अंतिम उपाय के रूप में इस मुद्दे को यह कहते हुए टाल दिया कि यदि उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई गई सामान्यीकरण की अवधारणा हमारी अंतरात्मा को संतुष्ट नहीं करती है, तो हम निर्णय में प्रस्ताव दे सकते हैं और आदेश दे सकते हैं कि परिस्थितियों में क्या किया जाए। यह तर्क हमें एक पुरानी कहावत की याद दिलाता है कि "वह सबसे दूर की यात्रा करता है जो नहीं जानता कि वह कहां जाता है"। हम नहीं जानते कि राज्य और उत्तरदाताओं के साथ क्या समस्या है। उन्हें सामान्यीकरण का सहारा क्यों लेना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हरियाणा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के छात्रों में नाराजगी थी? हमारा यात्रा करने का कोई इरादा नहीं है, सबसे दूर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस विषय पर कहां जाना है। बल्कि *आसिफ हमीत और अन्य* बनाम *जम्मू और कश्मीर सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है। कश्मीर और अन्य* (4) हमें उत्तर प्रदान करते हैं कि हम किसी भी राज्य कार्रवाई को प्रतिस्थापित करने का सहारा नहीं ले सकते हैं और इसे विधायिका या कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

वह संविधान के तहत अपने क्षेत्र के भीतर कार्य करे। इसलिए इस संबंध में, हम उत्तरदाताओं को कोई निर्देश जारी करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 की उपस्थिति में अपनी शक्ति के मापदंडों को जानना चाहिए।

(अठ्ठारह) हालांकि दो डिवीजन बेंच मामलों: *अर्चना सक्सेना* बनाम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक और अन्य *(5), और* मनु भंडारी *बनाम* पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (6) का हवाला देते हुए कहा गया था कि इस न्यायालय ने संस्थान ^ वरीयता के अनुसार उम्मीदवारों को अंकों की समानता द्वारा वेटेज के सिद्धांत को मान्यता दी थी, फिर भी ये मामले किसी भी पक्ष के मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं। उत्तरदाताओं के सकारात्मक मामले के लिए यह है कि सामान्यीकरण की अवधारणा का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वेटेज का अनुदान नहीं है और सकारात्मक रूप से कोई जैसा कि तत्काल मामले में इरादा नहीं है, जैसा कि दावा किया गया है।

(अठ्ठारह) एक अन्य मामले में *ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम और अन्य बनाम ठुकराल अंजलि देवकुमार और अन्य* (7) का हवाला देते हुए कहा गया था कि कॉलेज का पूर्व छात्र होने के आधार पर एक उम्मीदवार को महत्व देना मनमाना था। इस मामले को याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा इस आधार पर सेवा में डाला गया था कि सामान्यीकरण की अवधारणा में निहित महत्व देना स्पष्ट रूप से खंड 7 में दी गई गणितीय गणना के परिणामस्वरूप था। उस मामले में,

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज-वार संस्थागत वरीयता को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने अब तक केवल विश्वविद्यालय-वार संस्थागत वरीयता को मान्यता दी थी। लेकिन उस मामले में विश्वविद्यालय-वार संस्थागत वरीयता पर एक उम्मीदवार को दिए गए अंकों के महत्व को चुनौती नहीं दी गई थी, बल्कि यह कॉलेज-वार संस्थागत, पीफरेंस के अंकों का और अधिक महत्व था, जिसे चुनौती दी गई थी और सफलतापूर्वक हिट किया गया था। यह मामला हाथ में लिए गए मामले के निर्णय में कोई सहायता नहीं करता है।

(उन्नीस) पूर्वगामी कारणों से, यह याचिका सफल होती है। बेहिचक, हम संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करने वाली 'सामान्यीकरण' की अवधारणा और सिद्धांत को रद्द करते हैं और शैक्षणिक वर्ष 1989-90 के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और छोटू राम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुरथल में बी.टेक पाठ्यक्रमों में संयुक्त प्रवेश के लिए प्रवेश विवरणिका से इसे हटाने का निर्देश देते हैं, और उत्तरदाताओं को पुरानी प्रक्रिया के आधार पर प्रवेश को अंतिम रूप देने का निर्देश देते हैं। पिछले वर्षों में। याचिकाकर्ताओं की लागत 5,000 रुपये होगी।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468

के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्‌देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्‌देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्‌देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मयंक गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
चरखी दादरी, हरियाणा

(7) निर्णय आज 1989 (1) एससी 468